

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सख्या: 962

बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना

962. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री भोला सिंह:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है और प्राथमिकता कार्रवाई हेतु 12 देशों को चिह्नित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) क्या यह योजना एक कार्य बल द्वारा तैयार की गई थी जिसमें मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशन और इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारी शामिल थे;
- (घ) यदि हां, तो क्या कार्य बल ने उक्त 12 प्राथमिकता वाले देशों के लिए गतिविधियों हेतु कैलेंडर तैयार कर लिया है;
- (ङ) यदि हां, तो क्या यह योजना निर्यात-आयात प्रवृत्तियों, 20 से अधिक देशों में निवेश रुझान और उनके साथ रणनीतिक जुड़ाव के गहन विश्लेषण के बाद तैयार की गई है;
- (च) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का निवेश और व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों को शामिल करते हुए विभिन्न देशों में रोड शो आयोजित करने का विचार है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (छ): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तथा बहुपक्षीय और द्वीपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में नीति निर्धारण, कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ निर्यात संवर्धन, व्यापार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था और कतिपय निर्यात-मुखी उद्योगों तथा वस्तुओं का विनियमन करता है तथा मंत्रालय नई और आगामी प्रौद्योगिकी में निवेश की सुविधा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेजी लाने तथा उद्योग और व्यापार के संतुलित विकास में सहायता करके देश के औद्योगिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है।

मंत्रालय ने सभी हितधारक अर्थात् उद्योग मंडलों, निर्यात संवर्धन परिषदों, इन्वेस्ट इंडिया आदि के परामर्श से व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए एक गहन आउटरीच योजना तैयार की है।

यह कार्यनीति आयात-निर्यात रुझानों, आउटबाउंड निवेश प्रवृत्तियों और चुनिंदा प्राथमिकता वाले देशों के साथ कार्यनीतिक एंगेजमेंट, लक्षित दृष्टिकोण/पद्धति पर आधारित है, जिसमें

देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संकेतों, स्थानांतरण संकेतों, विविधीकरण कार्यनीति और एफडीआई आउटफ्लो के तुलनात्मक विश्लेषण संबंधी अनुसंधान शामिल है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संबंधित राज्य/देश के प्रमुख विकासोन्मुख क्षेत्रों पर अनुसंधान और जीडीपी समीक्षा दस्तावेजों और निर्यात रुझानों और इसकी क्षमता का अध्ययन किया गया था। निर्यात, व्यापार और निवेश क्षमता के आधार पर कई प्राथमिकता वाले देशों की पहचान की गई।

संबंधित देश/क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रमुख व्यापार आयोजनों/मेलों/रोड शो की पहचान भी इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई है।
